।। श्री गणेशाय नमः।।

हिन्दी पाक्षिक Fortnightly

Baat Hindustan ki

बात हिन्दुस्तान की

Baat Hindustan ki

RNI No.: WBHIN/2021/84049

विक्रम संवत 2083, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष चतुर्थी, 1-15 सितंबर 2026 (1-15 September 2026), वर्ष-6 (YEAR-6), अंक - 09, पृष्ठ - 4, मूल्य - ₹2, (PRICE- 2/-)

आरक्षण के मुद्दे पर आमने-सामने मोदी कैबिनेट के दो मंत्री, छिड़ी 'महाभारत'!

अजय कुमार झा: आरक्षण के मुद्दे पर बिहार की राजनीति से लेकर केंद्र की सत्ता तक सियासी तापमान बढ़ गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के भीतर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण में उप-वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के मुद्दे को लेकर दो प्रमुख सहयोगी दल आमने-सामने आ गए हैं। मोदी सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के बीच जुबानी जंग अब इतनी तीखी हो गई है कि मामला एक-दूसरे से इस्तीफा मांगने तक पहुंच गया है। आरक्षण को लेकर दोनों नेताओं की राय में गहरा मतभेद सामने आया है। एक तरफ जीतनराम मांझी दलित समाज के भीतर उन जातियों और वर्गों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए उप-वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जरूरत पर जोर दे रहे हैं, जो लंबे समय के बाद भी अपेक्षित लाभ से वंचित बताए जाते हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान इस विचार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि आरक्षण के भीतर इस तरह का वर्गीकरण दलित समाज की एकजुटता को कमजोर कर सकता है और इससे आरक्षण की मूल भावना प्रभावित होगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तेज हुई बहस

दरअसल, आरक्षण को लेकर यह बहस सुप्रीम कोर्ट के उस महत्वपूर्ण फैसले के बाद तेज हुई जिसमें अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की संवैधानिक वैधता पर चर्चा हुई। फैसले के बाद देशभर में यह सवाल उठने लगा कि क्या अनुसूचित जातियों को एक समान श्रेणी मानने के बजाय उनके भीतर सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक पिछड़े समूहों को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इसी बहस में क्रीमी लेयर का मुद्दा भी सामने आया। क्रीमी लेयर की अवधारणा मूल रूप से आरक्षण का लाभ उन अपेक्षाकृत संपन्न और आगे निकल चुके वर्गों तक सीमित करने से जुड़ी है, ताकि आरक्षण का लाभ समाज के उन तबकों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में क्रीमी लेयर का सवाल राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के भीतर भी अलग-अलग राय देखने को मिल रही है।

जीतनराम मांझी का तर्क- 'सबसे पिछड़े तक पहुंचे आरक्षण का लाभ'

केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी लंबे समय से दलित समाज के भीतर मौजूद सामाजिक असमानता का मुद्दा उठाते रहे हैं। उनका तर्क है कि अनुसूचित जातियों के भीतर भी सभी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ समूहों को आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ अपेक्षाकृत अधिक मिला है, जबकि कई जातियां अभी भी शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों के मामले में पीछे हैं। मांझी का मानना है कि यदि आरक्षण का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर और पिछड़े तबके को आगे लाना है, तो उन वर्गों की पहचान करना जरूरी है जिन्हें अब तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। उनके मुताबिक, केवल आरक्षण का प्रतिशत तय कर देना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना होगा कि उस आरक्षण का लाभ वास्तव में किन लोगों तक पहुंच रहा है। मांझी इसी आधार पर अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधानों की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि सामाजिक न्याय का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में सबसे ज्यादा वंचित हैं।

चिराग पासवान ने किया विरोध, दलित एकजुटता का दिया हवाला

वहीं, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान इस विचार के मुखर विरोध में हैं। चिराग का मानना है कि अनुसूचित जातियों को आरक्षण के भीतर अलग-अलग वर्गों में बांटना दलित समाज की राजनीतिक और सामाजिक एकजुटता को प्रभावित कर सकता है। चिराग पासवान की राजनीति का एक बड़ा आधार दलित और विशेष रूप से पासवान समुदाय के बीच उनकी पकड़ रही है। ऐसे में आरक्षण से जुड़े किसी भी ऐसे प्रस्ताव को लेकर उनका रुख बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे अनुसूचित जातियों के भीतर अलग-अलग समूहों के बीच नई राजनीतिक रेखाएं खिंच सकती हैं। चिराग का तर्क है कि आरक्षण व्यवस्था का मूल उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित और भेदभाव झेलने वाले समुदायों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। उनके अनुसार, आरक्षण के भीतर क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था लागू करने से पहले उसके व्यापक सामाजिक प्रभावों को समझना जरूरी है। इसी मतभेद ने अब एनडीए के भीतर दो सहयोगी दलों को आमने-सामने खड़ा कर दिया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर
AI की मदद से तैयार की गयी।

बात इस्तीफे तक पहुंची

आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के बीच मतभेद कोई सामान्य राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। विवाद तब और बढ़ गया जब चिराग पासवान ने सार्वजनिक रूप से जीतनराम मांझी के साथ-साथ उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे की मांग कर दी। चिराग का कहना था कि जो नेता दलित समाज के हितों के खिलाफ जाने वाला रुख अपना रहे हैं, उन्हें सत्ता में बने रहने के अपने नैतिक अधिकार पर विचार करना चाहिए। उन्होंने मांझी और संतोष सुमन से पद छोड़ने की मांग कर राजनीतिक बहस को सीधे सरकार में उनकी भूमिका से जोड़ दिया। चिराग के इस हमले के बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा कि क्या आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के भीतर मतभेद अब केवल वैचारिक स्तर तक सीमित रहेंगे या इसका असर गठबंधन की राजनीति पर भी दिखाई देगा।

मांझी ने भी पलटवार किया

चिराग पासवान की मांग पर जीतनराम मांझी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। मांझी ने चिराग की मांग को खारिज करते हुए कहा कि गरीबों और वंचितों के अधिकार की बात करना किसी पद से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। मांझी का स्पष्ट रुख है कि यदि समाज के भीतर सबसे कमजोर तबके तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच रहा है तो उस व्यवस्था में सुधार की बहस होनी चाहिए। उनका कहना है कि वे गरीबों और वंचितों के हित में अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटेंगे। मांझी ने चिराग की ओर से इस्तीफे की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी मांग करने से पहले व्यापक सामाजिक हित और गरीबों की वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चिराग पासवान से भी इस्तीफे की मांग कर दी। इस तरह आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुई वैचारिक बहस सीधे व्यक्तिगत और राजनीतिक टकराव में बदल गई।

एक ही गठबंधन, लेकिन आरक्षण पर अलग-अलग रास्ते

इस पूरे घटनाक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों नेता एक ही राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा हैं। चिराग पासवान और जीतनराम मांझी दोनों ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं और उनके दल बिहार में एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी माने जाते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं का सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलना एनडीए के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। बिहार की राजनीति में दलित वोट बैंक का विशेष महत्व है। राज्य में दलित समुदाय के भीतर भी अलग-अलग जातीय समूहों की अपनी राजनीतिक ताकत और सामाजिक पहचान है। ऐसे में आरक्षण में उप-वर्गीकरण का मुद्दा केवल संवैधानिक या प्रशासनिक बहस नहीं रह जाता, बल्कि इसका सीधा संबंध चुनावी राजनीति और सामाजिक समीकरणों से भी जुड़ जाता है। यही कारण है कि चिराग और मांझी के बीच आरक्षण को लेकर शुरू हुई बहस को बिहार की आगामी राजनीतिक दिशा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दलित राजनीति के भीतर नई बहस

आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण की बहस ने दलित राजनीति के भीतर भी कई सवाल खड़े किए हैं। एक पक्ष का तर्क है कि यदि आरक्षण का लाभ कुछ अपेक्षाकृत मजबूत समूहों तक ही सीमित रह जाता है तो सबसे पिछड़ी जातियों को न्याय नहीं मिल पाएगा। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि अनुसूचित जातियों के भीतर वर्गीकरण करने से ऐतिहासिक रूप से एकजुट हुए दलित समुदाय की राजनीतिक शक्ति कमजोर हो सकती है। यही दो दृष्टिकोण चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की राजनीति में भी दिखाई दे रहे हैं। मांझी जहां सबसे कमजोर तक लाभ पहुंचाने की दलील दे रहे हैं, वहीं चिराग दलित एकजुटता और आरक्षण की मूल भावना को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस अंतर को केवल दो नेताओं के व्यक्तिगत मतभेद के रूप में देखना आसान नहीं होगा। इसके पीछे बिहार के अलग-अलग दलित समुदायों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस भी जुड़ी हुई है।

बीजेपी के सामने गठबंधन प्रबंधन की चुनौती

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनडीए के भीतर पैदा हुए इस विवाद को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। दोनों नेता केंद्र की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और दोनों के अपने-अपने राजनीतिक आधार हैं। यदि यह विवाद आगे भी सार्वजनिक मंचों पर जारी रहता है तो इसका असर केवल चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के दलों के संबंधों पर नहीं, बल्कि बिहार में एनडीए के व्यापक सामाजिक समीकरण पर भी पड़ सकता है। बीजेपी के लिए चुनौती यह होगी कि वह एक तरफ अपने सहयोगी दलों की राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करे और दूसरी तरफ गठबंधन के भीतर किसी ऐसे मुद्दे को बड़ा होने से रोके, जिससे सामाजिक या चुनावी स्तर पर नुकसान की आशंका पैदा हो। खासकर बिहार जैसे राज्य में, जहां जातीय समीकरण चुनावी राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आरक्षण का मुद्दा किसी भी गठबंधन के लिए संवेदनशील हो सकता है।

क्या मोदी सरकार में बढ़ेगा दबाव?

चिराग पासवान और जीतनराम मांझी दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा हैं। ऐसे में दोनों के बीच बढ़ता विवाद केंद्र के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर सकता है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार या बीजेपी नेतृत्व की ओर से क्या रुख अपनाया जाएगा। राजनीतिक तौर पर यह उम्मीद जरूर की जा रही है कि गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व की ओर से दोनों पक्षों के बीच संवाद कायम करने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि आरक्षण जैसा मुद्दा केवल एक मंत्रालय या सरकार के प्रशासनिक फैसले तक सीमित नहीं है। यह सीधे सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों सहयोगी दलों के नेताओं को साथ लेकर चलने की होगी।

हनुमान बनाम मांझी की सियासी परीक्षा

चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी सहयोगी और कई मौकों पर उनका 'हनुमान' कहा जाता रहा है। दूसरी ओर जीतनराम मांझी बिहार की राजनीति के अनुभवी नेता हैं और लंबे राजनीतिक अनुभव के साथ केंद्र की सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच आरक्षण को लेकर पैदा हुआ विवाद राजनीतिक रूप से काफी दिलचस्प हो गया है। सवाल यह भी है कि यदि टकराव बढ़ता है तो बीजेपी नेतृत्व किस तरह दोनों नेताओं के बीच संतुलन बनाएगा। क्या पार्टी चिराग पासवान के साथ खड़ी दिखाई देगी, या फिर जीतनराम मांझी के उस तर्क को महत्व देगी जिसमें वे दलित समाज के सबसे पिछड़े वर्गों को आरक्षण का अधिक लाभ देने की बात कर रहे हैं? या फिर संभव है कि पार्टी दोनों पक्षों को साथ बैठाकर विवाद को शांत करने का रास्ता निकाले।

बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा असर

इस विवाद का सबसे बड़ा असर बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। राज्य में एनडीए का सामाजिक आधार कई अलग-अलग जातीय और सामाजिक समूहों के समर्थन पर टिका है। दलित राजनीति उसमें एक महत्वपूर्ण घटक है। चिराग पासवान की पार्टी का अपना मजबूत सामाजिक आधार है, जबकि जीतनराम मांझी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी दलित और महादलित राजनीति में अपनी अलग पहचान रखते हैं। ऐसे में यदि आरक्षण के मुद्दे पर दोनों दलों के बीच दूरी बढ़ती है तो इसका असर एनडीए के सामाजिक समीकरण पर पड़ सकता है। दूसरी ओर, यदि दोनों नेता अपने मतभेदों को गठबंधन की सीमा के भीतर रखते हुए अपनी-अपनी बात रखते हैं, तो यह विवाद अंततः एक व्यापक सामाजिक न्याय की बहस का रूप भी ले सकता है।

असली सवाल- आरक्षण का लाभ किसे और कैसे मिले?

पूरे विवाद के केंद्र में आखिरकार एक ही सवाल है-आरक्षण का लाभ समाज के सबसे वंचित व्यक्ति तक कैसे पहुंचे?

मांझी का तर्क है कि यदि किसी समुदाय के भीतर भी असमानता मौजूद है तो उस असमानता को दूर करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप जरूरी है। वहीं चिराग पासवान का कहना है कि इस तरह के हस्तक्षेप से कहीं ऐसा न हो कि आरक्षण का राजनीतिक और सामाजिक आधार ही कमजोर हो जाए। यानी दोनों नेता सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते अलग-अलग हैं। यही अंतर अब एनडीए के भीतर एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। अब नजर बीजेपी नेतृत्व के अगले कदम पर आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की आमने-सामने की लड़ाई फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। दोनों नेता अपने-अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहे हैं और मामला इस्तीफे की मांग तक पहुंच चुका है। अब सबकी नजर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर है। क्या शीर्ष नेतृत्व हस्तक्षेप कर दोनों सहयोगी दलों के बीच विवाद को शांत कराएगा? क्या दोनों नेताओं के बीच किसी समझौते का रास्ता निकलेगा? या फिर आरक्षण के इस संवेदनशील मुद्दे पर दोनों दल अपनी-अपनी राजनीतिक लाइन के साथ आगे बढ़ेंगे? फिलहाल इतना तय है कि आरक्षण के मुद्दे ने एनडीए के भीतर एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया है, जिसका असर केवल दिल्ली तक सीमित रहने वाला नहीं है। इसका सीधा प्रभाव बिहार की सामाजिक और राजनीतिक जमीन पर भी पड़ सकता है। **चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के बीच छिड़ी यह 'महाभारत' अब किस मोड़ पर पहुंचती है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन एक बात तय है-आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर बिहार की राजनीति के केंद्र में आ चुका है और एनडीए के भीतर इस पर सहमति बनाना शीर्ष नेतृत्व के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती साबित हो सकता है।**

नेपाल त्रासदी: ग्लेशियर और चट्टान के बड़े हिस्से के ढहने से आया मलबे का सैलाब, कुछ ही मिनटों में नदी ने लिया रौद्र रूप

नेपाल-चीन सीमा पर 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ ने हिमालयी क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। ग्लेशियर और चट्टान के बड़े हिस्से के अचानक ढहने के बाद आए मलबे के सैलाब ने गांवों, सड़कों, पुलों और बिजली परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाया। खबर लिखे जाने तक नेपाल में 800 से अधिक मौतें और करीब 2,500 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। चीन के तिब्बत क्षेत्र में भी 16 मौतें और सैकड़ों लोग लापता बताए गए हैं। राहत-बचाव अभियान जारी है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, आपदा की शुरुआत लांगटांग नेशनल पार्क के पास ग्लेशियर से जुड़ी तेज ढलान विफलता से हुई। बर्फ, चट्टान और मलबे का विशाल हिस्सा नीचे आकर ल्हेंडे खोला नदी में गिरा। इसके बाद मलबे और पानी का प्रवाह करीब 100 किलोमीटर तक नीचे पहुंचा और रास्ते में बसे इलाकों को प्रभावित किया।

शुरुआत में इस घटना को भूकंप से जोड़ा गया था, लेकिन बाद के वैज्ञानिक विश्लेषण में पाया गया कि जमीन में दर्ज कंपन संभवतः ग्लेशियर और चट्टान के ढहने से पैदा हुआ था। इसे करीब 5.2 तीव्रता के भूकंपीय संकेत के रूप में दर्ज किया गया, सामान्य विवर्तनिक भूकंप के रूप में नहीं।

इस आपदा में नदी में केवल पानी नहीं आया। उसके साथ बर्फ, चट्टान, मिट्टी और भारी मलबा भी तेजी से नीचे आया, जिससे सामान्य बाढ़ बेहद शक्तिशाली मलबा प्रवाह में बदल गई। इसके दबाव से सड़कें और पुल टूटे, घर तबाह हुए और हाइड्रोपावर परियोजनाओं को भी भारी नुकसान पहुंचा। कई कर्मचारी लापता हैं।

हिमालय पहले से भूस्खलन, हिमस्खलन और ग्लेशियर संबंधी आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील है। बढ़ते तापमान से ग्लेशियरों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की स्थिरता बदल रही है, जिससे ऐसे खतरों का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार किसी एक ग्लेशियर के टूटने को सीधे और अकेले जलवायु परिवर्तन का परिणाम बताना जल्दबाजी होगी।

इस त्रासदी ने हिमालयी क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रणाली की जरूरत फिर सामने ला दी है। केवल बारिश और नदी के जलस्तर की निगरानी पर्याप्त नहीं होगी। ग्लेशियरों की सैटेलाइट निगरानी, भूस्खलन सेंसर, भूकंपीय निगरानी और रियल-टाइम नदी चेतावनी प्रणालियों को साथ जोड़ना जरूरी होगा।

नेपाल की यह त्रासदी केवल एक देश की आपदा नहीं है। हिमालय से निकलने वाली नदियां भारत तक पहुंचती हैं। ऐसे में नेपाल, भारत और चीन के बीच समय पर सूचना साझा करने और संयुक्त आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करना बेहद जरूरी है।

नेपाल में ऐसी तबाही पहली बार नहीं, कई बार ग्लेशियर और बाढ़ बन चुके हैं काल

नेपाल की सबसे चर्चित ग्लेशियल बाढ़ों में **4 अगस्त 1985** की डिज त्शो (Dig Tsho) त्रासदी प्रमुख है। खुम्बू क्षेत्र में स्थित डिज त्शो झील में एक बड़े हिमस्खलन के गिरने से झील की प्राकृतिक बांध जैसी संरचना टूट गई और अचानक करीब 50 लाख घन मीटर पानी नीचे की ओर बह निकला।

जुलाई 1993 में मध्य नेपाल में रिकॉर्ड बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। **19 से 21 जुलाई** के बीच हुई अत्यधिक बारिश ने कई नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं तेज हो गईं।

2 अगस्त 2014 को सिंधुपालचोक जिले के जुरे में विशाल भूस्खलन हुआ। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर भोटेकोशी नदी में जा गिरा और नदी का रास्ता लगभग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। इसके बाद नदी के पीछे पानी जमा होने लगा और आसपास के इलाके में गंभीर खतरा पैदा हो गया।

15 जून 2021 को मेलम्ची क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। मेलम्ची और इंद्रावती नदियों में पानी और मलबे का प्रवाह बढ़ने से मेलम्ची बाजार समेत आसपास के इलाकों को भारी नुकसान हुआ। अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD) के अनुसार, इस घटना में पांच लोगों की मौत हुई और करीब 20 लोग लापता हुए। मेलम्ची जल आपूर्ति परियोजना को भी नुकसान पहुंचा और कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया।

16 अगस्त 2024 को एवरेस्ट क्षेत्र के थामे गांव में ग्लेशियल झील के फटने से अचानक बाढ़ आई। इस घटना में लोगों की मौत हुई, घर और हाइड्रोपावर परियोजना क्षतिग्रस्त हुई और ट्रेकिंग मार्ग भी प्रभावित हुआ। यह वही क्षेत्र है जहां 1985 में डिज त्शो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट ने बड़ी तबाही मचाई थी।

लाखों रुपये खर्च कर बना सार्वजनिक शौचालय बंद, बाहर हो रहा खुले में पेशाब

सोनी कुमारी झा: शहर को स्वच्छ और खुले में शौच एवं पेशाब से मुक्त रखने के उद्देश्य से सरकार की ओर से हावड़ा जिले में लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर जगह-जगह सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। लेकिन इन दिनों कई जगहों पर इन शौचालयों की स्थिति सरकारी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है।

हावड़ा के कई इलाके में बना सार्वजनिक शौचालय पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा है और उसके मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है। शौचालय बंद होने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, शौचालय के आसपास ही खुले में पेशाब किए जाने की शिकायत सामने आ रही है, जिससे इलाके में गंदगी और दुर्गंध का माहौल बना हुआ है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस उद्देश्य से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, शौचालय के आसपास कुछ कारोबारी दूध के कनस्तर रखकर अपना कारोबार करते नजर आ रहे हैं। इससे सार्वजनिक सुविधा की जगह का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं।

लोगों का कहना है कि जब सरकार स्वच्छता को लेकर लगातार अभियान चला रही है और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने पर जोर दिया जा रहा है, तो फिर लाखों रुपये खर्च कर बनाए गए शौचालयों पर ताला क्यों लगा है? स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द शौचालय को खुलवाने और परिसर को अतिक्रमण व व्यावसायिक इस्तेमाल से मुक्त कराने की मांग की है।

गौरतलब है कि 1 सितंबर से राज्य में खुले में शौच और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक से जुड़े नए नियम लागू किए जाने की बात कही गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल जुर्माना लगाने का भी प्रावधान बताया गया है। ऐसे में लोगों का सवाल है कि नियम लागू होने से पहले ही यदि सार्वजनिक शौचालय बंद पड़े रहें, तो स्वच्छता व्यवस्था को धरातल पर कैसे प्रभावी बनाया जाएगा?

अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब कार्रवाई करता है और बंद पड़े सार्वजनिक शौचालय को आम लोगों के लिए दोबारा कब खोला जाता है।

संक्षिप्त डायरी

7वें वेतनमान के लिए बिहार में शिक्षकों का डिजिटल अभियान, बोले- अब आश्वासन नहीं लाभ चाहिए

पटना (एजेंसी) बिहार में हैशटैग के साथ शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से समान वेतनमान की मांग की. शिक्षक नेताओं का कहना है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बावजूद सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा. अब शिक्षक सरकार से ठोस फैसले की मांग कर रहे हैं. बिहार के शिक्षकों ने सातवें वेतनमान की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसा डिजिटल अभियान चलाया कि देखते ही देखते शिक्षकों का मुद्दा दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया. बिहार शिक्षक मंच के आह्वान पर सुबह 11 बजे शिक्षकों ने हैशटैग के साथ ट्वीट करना शुरू किया और दावा है कि कुछ ही मिनटों में यह हैशटैग वर्ल्डवाइड नंबर-1 ट्रेंड करने लगा. इस डिजिटल मुहिम के जरिए शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से सीधे अपनी मांग रखी. शिक्षकों का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि सातवें वेतनमान का वास्तविक लाभ चाहिए. शिक्षक बोले- अब और नहीं चलेगा इंतजार डिजिटल कैंपेन का नेतृत्व कर रहे शिक्षक नेता अश्विनी पांडेय ने कहा कि शिक्षक पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ स्कूलों में काम कर रहे हैं. ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षकों को लेवल-6 से लेवल-8 तक का लाभ मिलना चाहिए. शिक्षकों का तर्क है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ-साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शिक्षकों को सातवें वेतनमान के अनुरूप पे-लेवल का लाभ मिल रहा है. जबकि बिहार में शिक्षकों के लिए अलग वेतन संरचना तैयार की गई है, जिससे वे खुद को दूसरे राज्यों के शिक्षकों की तुलना में पीछे महसूस कर रहे हैं. बिहार से जुड़ी अन्य ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें शिक्षकों का सवाल- राज्यकर्मी का दर्जा मिला फिर वेतनमान क्यों नहीं? शिक्षक नेताओं का कहना है कि सरकार ने सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी परीक्षा के जरिए शिक्षकों को सरकारी सेवा में शामिल कर राज्यकर्मी का दर्जा दिया है. लेकिन इसके बावजूद उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा. शिक्षकों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था, नई पेंशन योजना और सेवा शर्तों को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि सहायक शिक्षक के पुराने संवर्ग को समाप्त कर विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक जैसे नए संवर्ग बनाए गए हैं. वेतन के साथ इन मुद्दों पर भी नाराजगी शिक्षकों की मांग सिर्फ वेतन तक सीमित नहीं है. वे महंगाई के अनुरूप वेतन बढ़ाने, दूसरे राज्यों के बराबर वेतनमान देने और स्थानांतरण प्रक्रिया में भी राहत की मांग कर रहे हैं. शिक्षकों के मुताबिक स्थानांतरण के लिए नियमित शिक्षकों की तरह 30 स्कूलों के चयन का प्रावधान किया गया है.

दशहरा-दीपावली-छठ पर दिल्ली से बिहार आना होगा आसान, 120+ स्पेशल बसें चलेंगी

पटना (एजेंसी) दशहरा, दीपावली और छठ पर दिल्ली से बिहार के लिए 120 से ज्यादा स्पेशल और रेगुलर बसें चलाने की तैयारी है. सितंबर से बुकिंग शुरू हो सकती है, जबकि अक्टूबर से बसों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है. दशहरा, दीपावली और छठ पूजा में बिहार आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने वाली है. त्योहारों में ट्रेनों की बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग को देखते हुए दिल्ली, यूपी और बिहार के बीच 120 से ज्यादा स्पेशल और रेगुलर बसें चलाने की तैयारी है. परिवहन विभाग की योजना के मुताबिक बसों का परिचालन अक्टूबर से शुरू किया जा सकता है. दशहरा स्पेशल बसों की एडवांस बुकिंग अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है. वहीं, बुकिंग की प्रक्रिया सितंबर से शुरू हो सकती है, 60 स्पेशल डीजल और बसें चलेंगी त्योहारी सीजन में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. इसे देखते हुए करीब 60 स्पेशल डीजल और बसें चलाने की तैयारी है. खास बात यह है कि इन बसों का संचालन केवल दशहरा, दिवाली और छठ तक सीमित नहीं रहेगा. योजना के अनुसार सेवा को पूरे साल रोजाना जारी रखा जाएगा. इससे दिल्ली और बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों को नियमित बस सेवा का भी विकल्प मिलेगा. दिल्ली-बिहार के बीच 432 बसों का परमिट कोटा दिल्ली और बिहार के बीच बसों के संचालन के लिए

गोपालगंज में एयरपोर्ट का सपना होगा साकार? 517 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटा

पटना (एजेंसी) बिहार के गोपालगंज में सबेया एयरपोर्ट के विकास की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिससे हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीदें जगी हैं. 517 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटा दिया गया है और जिला प्रशासन ने अंतिम रिपोर्ट सिविल विमानन विभाग को भेज दी है. बिहार के गोपालगंज जिले के लोगों के लिए हवाई सेवा को लेकर बड़ी उम्मीद जगी है. सबेया एयरपोर्ट को विकसित करने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज होने के बाद यहां से विमान सेवा शुरू होने की संभावना बढ़ गई है. जिला प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट से जुड़ी फाइनल रिपोर्ट सिविल विमानन विभाग को भेजे जाने की जानकारी सामने आयी है. बिहार सरकार ने भी सबेया एयरपोर्ट के विकास को लेकर कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है. 16 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में हवाई कनेक्टिविटी की

समीक्षा के दौरान सबेया, गोपालगंज सहित अन्य प्रस्तावित हवाई सुविधाओं के विकास की दिशा में आवश्यक कार्रवाई तेज करने को कहा था. सरकार ने भूमि की उपलब्धता, स्थल की उपयुक्तता, यातायात की संभावनाओं और अन्य तकनीकी आवश्यकताओं का आकलन करने के निर्देश भी दिये हैं. 517 एकड़ जमीन से हटाया गया अतिक्रमण सबेया एयरपोर्ट को लेकर जिला प्रशासन ने जमीन खाली कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई की है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट की करीब 517 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली गयी है. इसके बाद एयरपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट सिविल विमानन विभाग को भेजी गयी है. प्रशासन की इस कार्रवाई को एयरपोर्ट के विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. हालांकि, एयरपोर्ट से नियमित यात्री विमान सेवा शुरू होने से पहले संबंधित विभागों की तकनीकी जांच, आवश्यक आधारभूत संरचना, सुरक्षा मानकों और विमानन कंपनियों से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी होना जरूरी होगा. सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है सबेया सबेया एयरपोर्ट गोपालगंज और आसपास के इलाकों के लिए लंबे समय से महत्वपूर्ण परियोजना माना जाता रहा है. एयरपोर्ट के विकसित होने से जिले के लोगों को हवाई यात्रा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री की समीक्षा में भी बिहार के छोटे शहरों और कम सेवा वाले क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़ने पर जोर दिया गया है. सरकार के अनुसार, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से आसपास के जिलों और महत्वपूर्ण पर्यटन, धार्मिक तथा आर्थिक केंद्रों को भी लाभ मिल सकता है. गोपालगंज के अलावा सीमावर्ती जिलों को भी मिलेगा फायदा सबेया एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने पर सिर्फ गोपालगंज ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों और सीमावर्ती इलाकों के लोगों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है. कम समय में दूसरे शहरों तक पहुंच आसान होने से व्यापारियों, छात्रों, मरीजों, नौकरीपेशा लोगों और दूसरे यात्रियों को सुविधा मिल सकती है. विशेष रूप से पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य बड़े शहरों से कनेक्टिविटी मिलने की स्थिति में लोगों को लंबी सड़क या रेल यात्रा के विकल्प के साथ हवाई यात्रा का विकल्प भी मिल सकेगा. हालांकि, किन शहरों के लिए उड़ानें शुरू होंगी, यह विमानन कंपनियों और संबंधित प्राधिकरणों की अंतिम मंजूरी तथा रूट निर्धारण के बाद ही स्पष्ट होगा. पर्यटन और व्यापार को मिल सकता है बड़ा फायदा गोपालगंज में हवाई सेवा शुरू होने का सीधा असर पर्यटन और स्थानीय कारोबार पर पड़ सकता है. जिले के धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक बाहर से आने वाले लोगों की पहुंच आसान हो सकती है. इससे होटल, परिवहन, स्थानीय बाजार, खान-पान और अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. बिहार की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें मरीजों और छात्रों के लिए भी आसान हो सकता है सफर हवाई सेवा शुरू होने पर गंभीर इलाज के लिए बड़े शहरों में जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए तेज आवागमन का एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हो सकता है विमानन कंपनियां और कितनी उड़ानें संचालित करती हैं. रोजगार और स्थानीय कारोबार को भी मिल सकता है सुरक्षा, ग्राउंड स्टाफ, परिवहन, पार्किंग, खान-पान, होटल, टैक्सी और अन्य सेवाओं में स्थानीय स्तर पर कारोबार बढ़ सकता है. इसके अलावा उद्योग और निवेश के लिए भी बेहतर कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

मंत्री विजय सिन्हा का ऐलान-जहरीला पेय वजह हो-ना हो, बाढ़ के चारों मृतकों को सरकार देगी सहायता

पटना (एजेंसी) बाढ़ के बेढ़ना गांव में कथित जहरीला पेय पदार्थ पीने से चार युवकों की मौत के मामले में कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने परिजनों से मुलाकात कर मदद का आश्वासन दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पटना के बाढ़ अनुमंडल थाना क्षेत्र के बेढ़ना गांव में कथित नॉनवेज पार्टी में जहरीला पेय पदार्थ पीने से चार युवकों की अचानक तबीयत बिगड़ने और बाद में मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. घटना की सूचना मिलने के बाद कृषि मंत्री विजय सिन्हा मृतकों के परिजनों से मिलने गांव पहुंचे. इस दौरान उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और हरसंभव मदद का भरोसा दिया. मौके पर मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बेढ़ना गांव

से उनका भावनात्मक जुड़ाव है. उन्होंने बताया कि इसी गांव के स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है. उन्होंने कहा कि इस तरह का माहौल और वातावरण गलत है. जहरीला पेय पदार्थ पीने की बात आई सामने मंत्री ने कहा कि लोगों की ओर से यह बात सामने आ रही है कि जहरीला पेय जैसा कोई पदार्थ मिला था और चारों युवकों ने उसका सेवन किया था. हालांकि, इसकी पुष्टि जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. पोस्टमार्टम से होगा खुलासा विजय सिन्हा ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट होगी और जांच के आधार पर प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा. यदि जांच में जहरीला पेय पदार्थ से मौत की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए बाढ़ के एसडीएम को आवश्यक निर्देश दिए हैं. चारों युवकों की इलाज के दौरान हुई मौत जानकारी के अनुसार चारों की अचानक तबीयत बिगड़ गई और देखते ही देखते सभी बेहोश हो गए. इसके बाद परिजन और ग्रामीण आनन-फानन में उन्हें बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद चारों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया. रास्ते में हुई मौत पटना ले जाने के दौरान इलाज के क्रम में चारों की मौत हो गई. मौत की सूचना मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. इसके बाद लोगों ने बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन को जाम कर हंगामा किया. ड्यूटी और रेफर करने की प्रक्रिया की भी होगी जांच कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि इस मामले को लेकर उनकी एसडीएम और डीएम से बात हुई है. एनटीपीसी में चारों करते थे काम विजय सिन्हा ने बताया कि चारों दोस्त एनटीपीसी में काम करते थे. मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से भी उनकी बात हुई है. उन्होंने पूछा है कि घटना के समय ड्यूटी पीरियड में कौन था और मरीजों को रेफर करने का काम किसने किया. इन सभी बिंदुओं की जानकारी ली जाएगी. मंत्री ने यह भी कहा कि रास्ते में मौत हुई है, तो इसकी भी जांच कराई जाएगी. आगे उन्होंने कहा कि पूरे मामले में सरकार कार्रवाई करेगी और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. जहरीला पदार्थ की पुष्टि हुई तो मिलेगा 4 लाख का मुआवजा मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने समय में जहरीला पेय पदार्थ से मौत होने पर 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का एलान किया था. उन्होंने कहा कि अगर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शराब की बात सामने आती है, तो मृतकों के परिवारों को यह मुआवजा मिलेगा. उन्होंने कहा कि अगर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शराब की पुष्टि नहीं होती है, तब भी मृतकों के परिवारों की मदद की जाएगी. इसके लिए मुख्यमंत्री से बात की जाएगी और परिवारों को सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा

संजय सिंह पर चिराग पासवान बोले- आरोप सही साबित हुए तो मंत्री पद ही नहीं, पार्टी से भी होगी बर्खास्तगी

पटना (एजेंसी) केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंत्री संजय सिंह पर लगे महिला से बदसलूकी के आरोपों पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जांच में आरोप सही पाए गए तो दोषी को सिर्फ मंत्री पद ही नहीं, बल्कि पार्टी से भी बर्खास्त किया जाएगा. चिराग ने साफ किया कि महिला सुरक्षा के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं होगा. बिहार सरकार के मंत्री और महुआ विधायक संजय सिंह पर महिला से कथित बदसलूकी के आरोपों को लेकर सियासत तेज है. अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि महिला सुरक्षा के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं होगा. चिराग पासवान ने कहा कि अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं और संबंधित व्यक्ति दोषी साबित होता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. उसे सिर्फ मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा, बल्कि पार्टी से भी

बर्खास्त किया जाएगा. आरोपी परिवार का हो, फिर भी कार्रवाई होगी. चिराग पासवान ने कहा कि गलत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया जा सकता. आरोपी चाहे उनके परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, अगर उसने किसी महिला के साथ बदतमीजी की है तो मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जांच के बाद अगर आरोप सही साबित होते हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं होगी. दोषी साबित हुए तो पार्टी से भी बाहर केंद्रीय मंत्री ने अपने रुख को और स्पष्ट करते हुए कहा कि दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को सिर्फ मंत्री पद से हटाना ही पर्याप्त नहीं होगा. मंत्री पद के साथ पार्टी की सदस्यता भी खत्म की जाएगी. चिराग के इस बयान को इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि संजय सिंह बिहार सरकार में मंत्री हैं. ऐसे में उनके बयान से साफ है कि महिला सुरक्षा और पार्टी अनुशासन के मुद्दे पर वह सख्त रुख अपना रहे हैं. तेज प्रताप के आरोपों से शुरू हुआ पूरा विवाद दरअसल, संजय सिंह को लेकर विवाद तेज प्रताप यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद शुरू हुआ. तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि दिल्ली दौरे के दौरान एक बड़े होटल में संजय कुमार सिंह ने एक महिला कर्मचारी के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया. उन्होंने महिला के शोषण के प्रयास का भी आरोप लगाया था.तेज प्रताप ने सरकार और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है. संजय सिंह ने आरोपों को खारिज किया है और इसी मामले में तेज प्रताप यादव को कानूनी नोटिस भी भेजा है. बिहार की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें संजय सिंह ने तेज प्रताप को भेजा 50 करोड़ का नोटिस संजय सिंह की ओर से अधिवक्ता सुशील कुमार ने 30 अगस्त को तेज प्रताप यादव को कानूनी नोटिस भेजा था. नोटिस में सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए गए आरोपों को झूठा और मानहानिकारक बताया गया है. तेज प्रताप से संबंधित पोस्ट हटाने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और भविष्य में इस तरह के आरोप नहीं लगाने की मांग की गई है. नोटिस में 50 करोड़ रुपये के मानहानि दावे की चेतावनी भी दी गई है. तेज प्रताप बोले थे- शेर का बेटा हूं, डरने वाला नहीं नोटिस और विवाद के बीच तेज प्रताप यादव ने भी पलटवार किया था. उन्होंने कहा था, मैं शेर का बेटा हूं, डरने वाला नहीं. तेज प्रताप ने कहा था कि मंत्री हैं तो घर आकर बात करें. उन्होंने यह भी कहा था कि वह सच्चाई सामने लाकर रहेंगे. अब चिराग पासवान के बयान के बाद इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है.

जहरीले पेय पदार्थ पीने से 4 लोगों की मौत पर तेजस्वी ने की इंक्वायरी की मांग, बोले- सिर्फ गरीब ही मारे जा रहे

पटना (एजेंसी) बिहार के बाढ़ में जहरीले पेय पदार्थ पीने से चार लोगों की मौत का मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इंक्वायरी की मांग कर दी है. साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि प्रशासन कुछ नहीं देख रहा है. पटना के बाढ़ में जहरीले पेय पदार्थ पीने से हुई मौतों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी लेकिन प्रशासन प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाया. कानून-व्यवस्था पर सवाल किए खड़े आगे उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है और लगातार गंभीर घटनाएं हो रही हैं. लेकिन प्रशासन कुछ नहीं देख रहा है. घटनाएं कैसे हो रही हैं, यह प्रशासन ही बताएगा. लगातार गरीब ही मारे जा रहे हैं. गरीबों को ही जेल भेजा जा रहा है. तेजस्वी ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. इस तरह से बिहार में हुए चार लोगों की मौत के बाद सियासत में भी चर्चा तेज हो गई है. घटना की सूचना मिलने के बाद कृषि मंत्री विजय

सिन्हा मृतकों के परिजनों से मिलने गांव पहुंचे. इस दौरान उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और हरसंभव मदद का भरोसा दिया. बिहार से जुड़ी अन्य ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें विजय सिन्हा ने को दिए आदेश मंत्री ने कहा कि लोगों की ओर से यह बात सामने आ रही है कि जहरीले पेय जैसा कोई पदार्थ मिला था और चारों युवकों ने उसका सेवन किया था. लेकिन इसकी पुष्टि जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. जांच के आधार पर प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा. यदि जांच में जहरीले पेय पदार्थ से मौत की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए बाढ़ के एसडीएम को आवश्यक निर्देश दिए हैं. की बैठक पर भी किया रिएक्ट दूसरी तरफ, की बैठक को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि संगठन को मजबूत करने और आगे के कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा होगी.

तेज प्रताप बोले- शेर का बेटा हूं, डरने वाला नहीं, संजय सिंह ने थमा दिया 50 करोड़ का मानहानि नोटिस

पटना (एजेंसी) तेज प्रताप यादव और मंत्री संजय कुमार सिंह के बीच विवाद अब कानूनी नोटिस तक पहुंच गया है. तेज प्रताप ने कहा- शेर का बेटा हूं, डरने वाला नहीं. इसके बाद संजय सिंह ने उन्हें 50 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है. मामला कथित होटल कांड के आरोपों से जुड़ा है. बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मंत्री संजय कुमार सिंह के बीच विवाद अब कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है. संजय सिंह की ओर से तेज प्रताप यादव को 50 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा गया है. मंत्री के अधिवक्ता सुशील कुमार ने 30 अगस्त 2026 को यह नोटिस जारी किया. इसमें तेज प्रताप के सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए गए आरोपों को झूठा और मानहानिकारक बताया गया है. नोटिस में तेज प्रताप से संबंधित पोस्ट हटाने, सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने और भविष्य में ऐसी टिप्पणी नहीं करने का लिखित आश्वासन देने की मांग की गई है. महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार का लगाया था आरोप पूरा विवाद तेज प्रताप यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ. तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि दिल्ली दौरे के दौरान एक बड़े होटल में संजय कुमार सिंह ने एक महिला कर्मचारी के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया. उन्होंने पोस्ट में मंत्री पर महिला के शोषण का प्रयास करने का भी आरोप लगाया था. तेज प्रताप ने इस मामले को गंभीर बताते हुए सरकार और प्रशासन से निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की थी. 25 लाख रुपये के लेन-देन का भी दावा तेज प्रताप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक और गंभीर दावा किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि मामले को दबाने और रफा-दफा करने के लिए कथित तौर पर 25 लाख रुपये का लेन-देन किया गया. तेज प्रताप ने इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की बात कही थी. वहीं, संजय सिंह की ओर से भेजे गए नोटिस में इन आरोपों को झूठा बताया गया है. संजय सिंह बोले थे- सबूत दे दो, राजनीति छोड़ दूंगा तेज प्रताप के आरोपों के बाद संजय कुमार सिंह ने भी पलटवार किया था. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा था कि अगर कोई सबूत पेश कर दे, तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे. इसके बाद विवाद और बढ़ गया. तेज प्रताप ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री के बयान पर जवाब दिया. तेज प्रताप बोले- 'मैं शेर का बेटा हूं, डरने वाला नहीं' प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज प्रताप ने कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने खुद को 'शेर का बेटा' बताते हुए कहा कि वह पीछे हटने वाले नहीं हैं. प्रताप ने कहा था कि हर कोई 'माई का लाल' होता है. उन्होंने संजय सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह मंत्री हैं तो घर आकर बात कर लें. उन्होंने साफ कहा था कि वह इस मामले की सच्चाई सामने लाकर रहेंगे. ब संजय सिंह ने भेजा 50 करोड़ का नोटिस विवाद बढ़ने के बाद संजय सिंह की ओर से कानूनी नोटिस भेजा गया है. अधिवक्ता सुशील कुमार की ओर से जारी नोटिस में तेज प्रताप के सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया गया है. नोटिस में तेज प्रताप से सात दिनों के भीतर संबंधित पोस्ट हटाने की मांग की गई है. साथ ही उनसे सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया है. भविष्य में इस तरह की टिप्पणी दोबारा नहीं करने का लिखित आश्वासन देने की मांग भी की गई है. नोटिस में तेज प्रताप से जुड़े दूसरे मामलों का भी जिक्र संजय सिंह के नोटिस में सिर्फ होटल विवाद का जिक्र नहीं है. इसमें तेज प्रताप से जुड़े दूसरे निजी और राजनीतिक विवादों का भी उल्लेख किया गया है. नोटिस में ऐश्वर्या, अनुष्का, मिशु और मोनिका समेत कई नामों का जिक्र करते हुए तेज प्रताप से सवाल किए गए हैं. नोटिस के जरिए पूछा गया है कि इन मामलों को लेकर तेज प्रताप की क्या सफाई है. साथ ही उन महिलाओं के लिए न्याय की मांग की गई है, जो कथित तौर पर इन मामलों में न्याय चाहती हैं. बिहार की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें 'दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए' नोटिस में तेज प्रताप को निशाने पर लेते हुए कहा गया है कि 'जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए.' इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि दूसरों पर गंभीर आरोप लगाने से पहले तेज प्रताप को अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहिए. संजय सिंह की ओर से भेजे गए नोटिस में इसी आधार पर तेज प्रताप से अपने आरोपों पर सफाई देने और माफी मांगने की मांग

की गई है. सात दिन में जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? कानूनी नोटिस में तेज प्रताप को सात दिनों का समय दिया गया है. इस दौरान पोस्ट हटाने, माफी मांगने और भविष्य में ऐसी टिप्पणी नहीं करने का लिखित आश्वासन देने को कहा गया है. मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में संजय सिंह की ओर से आगे कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इसमें 50 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा भी शामिल है. तेज प्रताप की अगली प्रतिक्रिया पर नजर फिलहाल मामला आरोप, पलटवार और कानूनी नोटिस के बीच पहुंच गया है

सपा सरकार बनने पर खंगार समाज को मिलेगा राजनीतिक सम्मान, खोले जाएंगे बंद विद्यालय : अखिलेश यादव

एजेंसी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर महाराजा खेत सिंह खंगार के समाज के लोगों को राजनीतिक सम्मान और उचित स्थान देकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया जाएगा। उन्होंने एक फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा प्रदेश में बंद किए जा रहे परिषदीय विद्यालयों का दावा किया और कहा कि सपा सरकार बनने पर बंद स्कूलों को फिर से चालू कराया जाएगा। अखिलेश यादव रविवार को राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमहाराजा खेत सिंह खंगार जी के समाज के लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी, उन्हें राजनीतिक सम्मान और स्थान देकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लोगों की मांग रही है कि जातीय जनगणना कराई जाए और आबादी के अनुपात में सभी वर्गों को उनका हक और सम्मान मिले। अखिलेश ने कहा उप्र में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही तीन महीने के भीतर जातीय जनगणना कराने का काम किया जाएगा। सपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में लूट और हमला डकैतीह हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार में हो रही इस लूट को रोककर जो पैसा बचेगा, उसे गरीबों के हित में खर्च किया जाएगा। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हपूरा देश जानता है कि सीता मां को चुराने वाला भेष बदलकर आया था, इसलिए ऐसे (भाजपा) के लोगों से सावधान रहिए। उन्होंने प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को बंद किए जाने का भी आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जिन 26 हजार प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उन्हें फिर से चालू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों के बंद होने से गरीब, ग्रामीण और वंचित परिवारों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी तथा उन्हें शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। सपा सरकार बनने पर पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समाज को उसकी आबादी के अनुपात में हक और सम्मान देने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समान अवसर के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार बनने पर वंचित वर्गों को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़े धन्ना सेठों की पार्टी है, गरीबों से पैसा लूटकर उनकी जेबों तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा छवि सुधारने के लिए 07 हजार करोड़ खर्च किया जा रहा, सच्चाई तो ये है कि 70 हजार करोड़ भी खर्च कर दें छवि सुधरने वाली नहीं है। अखिलेश ने फिर दोहराया कि पीडीए से उन्हें (भाजपा) पेट दर्द है, क्योंकि हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। सपा अध्यक्ष ने बिना नाम लिए कहा कि चौधरी चरण सिंह जो पहले नेता थे जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया, अगर उनका सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी तो हैंडपंप को तीन गुना सीटें दी जाएं।

संक्षिप्त डायरी

प्रोजेक्ट नई किरण से फिर मिले 11 बिखरे परिवार

एजेंसी

औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती के निर्देशन में महिला थाना औरैया में प्रोजेक्ट नई किरण के तहत परिवार परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला थाना प्रभारी पूजा राठौर ने की। इस दौरान ऐसे 11 परिवारों के मामलों की सुनवाई की गई, जो आपसी वैचारिक मतभेद और पारिवारिक विवादों के चलते लंबे समय से अलग रह रहे थे। पति-पत्नी के बीच बढ़ती दूरियों के कारण परिवार टूटने की स्थिति में पहुंच गए थे। महिला थाना पुलिस एवं प्रोजेक्ट नई किरण की टीम ने दोनों पक्षों को समझाकर उनके बीच चल रहे मनमुटाव और कलह को दूर करने का प्रयास किया। काउंसलिंग के बाद सभी 11 परिवार एक साथ रहने के लिए राजी हो गए। इसके बाद पति-पत्नी की आपसी सहमति के साथ पुनः एकजुट कर उनके परिवारों के साथ हंसी-खुशी विदा किया गया। महिला थाना प्रभारी पूजा राठौर ने बताया कि प्रोजेक्ट नई किरण का उद्देश्य पारिवारिक विवादों को बातचीत और आपसी समझदारी के माध्यम से सुलझाकर बिखरते परिवारों को एक सूत्र में बांधना है। उन्होंने कहा कि यह पहल समाज में पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सड़क हादसे में घायल किसान की वाराणसी में इलाज के दौरान मौत, परिवार में मचा कोहराम

एजेंसी

मीरजापुर। राजगढ़ थाना क्षेत्र के धौरहा गांव के पास शनिवार को दो बाइकों की आमने-सामने हुई भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल युवक की रविवार दोपहर वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। धनावल गांव निवासी 35 वर्षीय सरविंद खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। शनिवार को वह बाइक से अपने घर लौट रहा था। धौरहा गांव के पास सामने से आ रही बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में सरविंद गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा, जबकि दूसरी बाइक पर सवार युवक को मामूली चोटें आईं और वह मौके से चला गया। ग्रामीणों ने घायल सरविंद को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। वहां रविवार दोपहर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई अरविंद ने बताया कि सरविंद दो भाइयों में छोटा था। उसके परिवार में पत्नी किरन के अलावा पांच वर्षीय और डेढ़ वर्षीय दो मासूम बेटे हैं। शव घर पहुंचते ही बच्चों और परिजन की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। राजगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक बाल मुकुंद मिश्र ने घटना की जानकारी से अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

पांच मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि, जिला चिकित्सालय में बना वार्ड

एजेंसी

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में स्वाइन फ्लू का संक्रमण लगातार अपने पैर पसार रहा है। जिले में पांच मरीजों में स्वाइन फ्लू के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। रविवार को जिला चिकित्सालय में स्वाइन फ्लू की दृष्टिगत बनाए गए वार्ड में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने चिकित्सीय व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि जिला अस्पताल की टीम संक्रमित मरीजों के घर गई और सभी को दवाई दी गई है। इसके साथ ही सभी मरीजों से होम आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया है। टीम ने पहले सभी संक्रमित मरीजों से फोन पर बात की थी, कोई भी खतरे की स्थिति में नहीं था। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के पास इससे निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं। अब तक मिले स्वाइन फ्लू के मरीज से बात करने पर पता चला है कि मरीजों में दूसरे शहर से आने-जाने या किसी पार्टी और सार्वजनिक आयोजन में शामिल होने के बाद बीमारी के लक्षण दिखाई दिए। हालांकि इनमें एक डॉक्टर भी शामिल है जिसके मरीज के संपर्क में आने से संक्रमित होने की आशंका है। इससे संक्रमण के स्रोत और संपर्क में आए लोगों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि समय रहते संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान और जांच नहीं हुई तो संक्रमण की चेन आगे बढ़ सकती है।

दो बाइकों की आमने-सामने हुई भिड़ंत में युवक की मौत

एजेंसी

मुरादाबाद। राजगढ़ थाना क्षेत्र के धौरहा गांव के पास शनिवार को दो बाइकों की आमने-सामने हुई भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल युवक की रविवार दोपहर वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। धनावल गांव निवासी 35 वर्षीय सरविंद खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। शनिवार को वह बाइक से अपने घर लौट रहा था। धौरहा गांव के पास सामने से आ रही बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में सरविंद गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा, जबकि दूसरी बाइक पर सवार युवक को मामूली चोटें आईं और वह मौके से चला गया। ग्रामीणों ने घायल सरविंद को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया।

सीट के विवाद को लेकर ट्रेन पर की थी पत्थरबाजी, जीआरपी ने 6 को पकड़ा, 4 को भेजा जेल

एजेंसी

वाराणसी। वाराणसी-प्रयागराज रेलखंड पर मेमो ट्रेन में पत्थरबाजी करने के मामले में जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर जांच करते हुए जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने छह आरोपियों को पकड़ लिया। इनमें चार बालिग और दो नाबालिग शामिल हैं। बालिग आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया, जबकि दोनों नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। जीआरपी सीओ कुंवर प्रभात सिंह के अनुसार, 28 अगस्त को वाराणसी से प्रयागराज जा रही मेमो ट्रेन पर भदोही जिले के अहिरमनपुर हॉल्ट के पास कुछ युवकों ने पत्थरबाजी की थी। घटना के दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों से युवकों का विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपियों ने ट्रेन को निशाना बनाते हुए पत्थर फेंके। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे सुरक्षाबल के संज्ञान में आया। वीडियो सामने आने के बाद जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने उसे जांच का आधार बनाया। वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान के लिए स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई गई और संभावित आरोपियों को चिन्हित किया गया। जांच के दौरान टीम को आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके बाद दबिश देकर छह युवकों को पकड़ लिया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की संलिप्तता सामने आई। चार आरोपियों की उम्र बालिग होने की पुष्टि होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं, दो आरोपियों के नाबालिग पाए जाने पर उनके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए बाल सुधार गृह भेजा गया।

भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने सपा के पीडीए को बताया छलावा, 2027 चुनाव का किया आह्वान

एजेंसी

वाराणसी। पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के भानपुर में भाजपा नेता रविशंकर सिंह की ओर से आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के काशी क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने कार्यकर्ताओं से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ हैं और बूथ स्तर पर उनकी सक्रियता ही पार्टी की मजबूती का आधार है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अशोक चौरसिया ने समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले को छलावा बताया। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव समय-समय पर पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हैं। कभी इसमें ब्राह्मणों को प्रमुखता दी जाती है तो कभी पिछड़ों को, आगे भी यह फार्मूला बदल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास अपना कोई ठोस मुद्दा नहीं है और जनता उसके शासनकाल को देख चुकी है। उन्होंने दावा किया कि जनता का विश्वास भाजपा के साथ है और 2027 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। वाराणसी की सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत का भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बूथ स्तर पर मेहनत करने वाला कार्यकर्ता संगठन में उच्च पद तक पहुंच सकता है। अमित शाह का उदाहरण देते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। करीब एक घंटे तक चले संवाद कार्यक्रम में उन्होंने चुनावी रणनीति, बूथ प्रबंधन, मतदाता सूची की निगरानी और संगठन को मजबूत करने सहित विभिन्न विषयों पर कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश दिए। साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सक्रियता बढ़ाने को कहा। भाजपा जिलाध्यक्ष रामसकल पटेल ने कहा कि उन्होंने 1993 से भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और पार्टी ने उन्हें वाराणसी का जिलाध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ईमानदारी से चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान करते हुए कहा कि एक बार फिर भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कार्यक्रम के आयोजक भाजपा नेता रविशंकर सिंह ने मुख्य अतिथि अशोक चौरसिया और अन्य अतिथियों का अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न देकर स्वागत-सम्मान किया।

इस वर्ष के अंत तक स्वच्छ हो जाएगी गोमती नदीः मुख्यमंत्री

एजेंसी

लखनऊ। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में अटल जी के सपनों को साकार किया गया है। लखनऊ में संकरी गलियां हैं तो सीएम ग्रिड की स्मार्ट रोड भी है। किसान पथ जैसा आउटर रिंग रोड भी है। यहां ऊदा देवी पासी व महाराजा बिजली पासी के स्मारकों की धरोहर है तो दूसरी ओर लखनऊ भारत की रक्षा आवश्यकता व आत्मनिर्भरता की दृष्टि से ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइलों का केंद्र भी बना है। यहां हस्तशिल्पियों की चिकनकारी की अद्भुत कला है तो यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता देकर लखनऊ को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। सीएम ने कहा कि 2017 के पहले जिस प्रदेश के सामने पहचान का संकट, अभाव, अराजकता, अव्यवस्था, उपद्रव था, आज वह प्रदेश इन सबसे उबर चुका है। हमने 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश को नई दिशा देने का प्रयास किया है। अब यूपी भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेकथ्रू बनकर ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता के लिए यूपी में छह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी स्थापित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है। देश में जितने भी एक्सप्रेसवे हैं, इनमें 60 फीसदी यूपी के पास हैं। यहां रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क, सर्वाधिक मेट्रो भी हैं। सीएम ने भारत सरकार से मेट्रो के द्वितीय चरण की स्वीकृति दिलाने के लिए रक्षा मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह कार्य भी बहुत जल्द आगे बढ़ने जा रहा है। देश की पहली रैपिड रेल, पहला वाटर-वे और सबसे बड़ा एयरकनेक्टिविटी नेटवर्क यूपी के पास है। यहां 17 घरेलू व 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। यूपी से देश-दुनिया के सभी क्षेत्रों में एयर कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध है। सैन्य बलों में यूपी की लीडिंग पोजिशन सीएम ने कहा कि सैन्य बलों की सेवाओं में यूपी हमेशा लीडिंग पोजिशन में रहा है। देश में सैनिक स्कूलों की परंपरा की शुरुआत डॉ. संपूर्णानंद ने यूपी से की थी। यूपी में बने कई सैनिक स्कूल युवाओं को तैयार कर रहे हैं, जो वर्तमान के साथ ही भविष्य के भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देंगे। हमारी सेना के अधिकारी व जवान 24 घंटे अनवरत भारत की रक्षा करते है

'मन की बात' का 137वां प्रसारणः 938 से अधिक बूथों पर 9 हजार से अधिक लोगों ने सुना पीएम का संबोधन

एजेंसी

मुरादाबाद। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुरादाबाद महानगर के उपाध्यक्ष व मन की बात कार्यक्रम के महानगर संयोजक नवदीप टंडन ने बताया कि आज मन की बात कार्यक्रम का 137वां संस्करण नगर व देहात विधानसभा के 938 से अधिक बूथों पर 9,312 से अधिक लोगों ने सुना। मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने बताया कि आज मन की बात कार्यक्रम के 137वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत", यह अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है- नशामुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत से लोग, खासकर युवा, इसका बड़ा हिस्सा बन रहे हैं। जिसके चलते उनके परिवार को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हमें युवाओं को संभालना होगा। इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला, महानगर के उपाध्यक्ष व मन की बात कार्यक्रम के महानगर संयोजक नवदीप टंडन, क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा, नगर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी डॉ जयपाल सिंह व्यस्त व गोपाल अंजान, प्रांतीय परिषद सदस्य निमित जायसवाल, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की महानगर संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता, महानगर महामंत्री विशाल त्यागी, अमित शर्मा, शम्मी भटनागर, मीडिया प्रभारी अर्पित गुप्ता व भरत टंडन, पार्षद दल के उप नेता सुरेंद्र बिश्नोई, नगर निगम कार्यकारिणी उपाध्यक्ष शैलेंद्र सैनी, हेमराज सैनी, मनीष गुर्जर, अशोक सैनी, सुनीता शर्मा, विजयलक्ष्मी पंडित, वनिता मेहरोत्रा, हिमांशु और दीक्षांत चौधरी, दीपक चौधरी, अभिषेक चौबे, अश्विनी शर्मा, हरिओम सैनी, सुमित चौहान, गौरव सक्सेना सहित भाजपा महानगर पदाधिकारी, मोर्चों और विभागों के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी, मंडल कार्यकारिणी, बूथ अध्यक्ष, बूथ कार्यकारिणी, कार्यकर्ताओं ने विभिन्न बूथों और शक्ति केंद्रों पर मन की बात कार्यक्रम सुना व देखा।

उप्र में 100 रेलवे एवं 100 बस स्टेशनों सहित पांच हवाई अड्डों पर खोलेंगे मुख्यमंत्री महिला उत्पाद विपणन केंद्र

एजेंसी

लखनऊ।केशव प्रसाद मौर्य ने महिला विपणन केंद्र के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दिए निर्देश तीन करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने और 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाने के लक्ष्य को पूरा करें अधिकारी लखनऊ, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी ली, धरातलीय आंकड़े नहीं मिले सन्तोष जनक दिए दूरभाष पर कड़े निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन एवं ब्रांडिंग के लिए विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर 543 प्रेरणा सरस स्टोर स्थापित किए गए तथा तीन हजार से अधिक उत्पादों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन विपणन प्लेटफार्म से जोड़ा गया। इन उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि महिलाओं को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो। उन्होंने विकेंद्रीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में महिला सहभागिता बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि लखपति दीदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कर महिलाओं को सौर ऊर्जा आधारित गतिविधियों से जोड़ा जाए। उद्योगों एवं उद्यमियों को सौर ऊर्जा के लाभों की जानकारी देकर सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशन कार्य को बढ़ावा दिया जाए। उप मुख्यमंत्री ने ड्रोन दीदी योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि 75 जिलों में 11,81,660 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ड्रोन सखियों का चयन किया गया है तथा प्रथम चरण में दीदीयों को 114 ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि ड्रोन तकनीक से किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग घटाने और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाए।उन्होंने टेक होम राशन योजना को सभी 75 जनपदों तक शीघ्र विस्तारित करने के निर्देश दिए। वर्तमान में 43 जनपदों में 204 इकाइयां संचालित हैं, जिनमें लगभग 4,000 सदस्य कार्यरत हैं। उपमुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन एवं मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक समूह की दीदियों को जोड़ने के निर्देश दिए। केशव प्रसाद मौर्य ने मिशन निदेशक को 03 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने तथा 01 करोड़ लखपति दीदियां बनाने के लक्ष्य पर मिशन मोड में कार्य करने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कि हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री महिला उत्पादन विपणन योजना के तहत 75 जनपदों के 826 विकास खंडों, 100 रेलवे एवं 100 बस स्टेशनों तथा 05 हवाई अड्डों पर केंद्रों की स्थापित करेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डबल इंजन सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनके परिवारों में खुशहाली लाना है।

हावड़ा स्टेशन के आसपास होटल और लॉज में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

हावड़ा स्टेशन से सटे होटल और लॉज लगभग जतुगृह में तब्दील हो चुके हैं। कई जगहों पर रिहायशी मकानों का इस्तेमाल होटल के रूप में किया जा रहा है। संकरे कमरों में बाहर से आने वाले मेहमानों को ठहरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पुराने मकानों में जगह-जगह बिजली के कटे-फटे तार लटक रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है।

दमकल विभाग के अग्निशमन कानूनों की खुलेआम अनदेखी करते हुए हावड़ा स्टेशन के आसपास स्थित होटलों में धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है। यहां छोटे-बड़े मिलाकर करीब 200 होटल हैं।

स्टेशन से सटे डब्सन लेन की एक पांच मंजिला इमारत की प्रत्येक मंजिल पर अलग-अलग लॉज या होटल संचालित हो रहे हैं। पहले यह इमारत रिहायशी मकान थी, लेकिन वर्तमान में पूरी इमारत का इस्तेमाल होटल के रूप में किया जा रहा है। हावड़ा स्टेशन के नजदीक होने के कारण इन होटलों में पूरे साल मेहमानों की भीड़ लगी रहती है।

दमकल नियमों के अनुसार इन होटलों की सीढ़ियों की चौड़ाई 2.50 मीटर होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनकी चौड़ाई एक मीटर भी नहीं है। पांच मंजिला इमारत में नियम के मुताबिक कम से कम दो निकास (एग्जिट) होने चाहिए, लेकिन यहां मेहमानों के आने-जाने के लिए एक ही सीढ़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

नियमों के अनुसार छत पर 10,000 लीटर क्षमता का पानी का टैंक या अंडरग्राउंड रिजर्वायर होना चाहिए, लेकिन यहां इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। न तो स्प्रिंकलर हैं, न होज पाइप और न ही फायर अलार्म सिस्टम। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने का उचित रास्ता नहीं होने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहां के कर्मचारियों का भी यही मानना है।

कई छोटे लॉज और होटलों के पास तो दमकल विभाग का लाइसेंस तक नहीं है।

हालांकि दमकल विभाग की ओर से दावा किया गया है कि इन होटलों को समय-समय पर नोटिस दिया जाता है और अग्निशमन व्यवस्था की जांच भी की जाती है। वहीं, होटल कर्मचारियों का कहना है कि दमकलकर्मी निरीक्षण के लिए यहां आते ही नहीं हैं।

तारापीठ और कोलकाता के होटलों में आग लगने की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में यदि हावड़ा स्टेशन से सटे होटलों पर प्रशासन की ओर से समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो यहां भी कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

जानकारी के अनुसार, हावड़ा शहर के करीब 37 होटलों को दमकल अधिकारियों की ओर से नोटिस जारी किया गया है। दमकल विभाग के सूत्रों के मुताबिक, जिन होटलों में पर्याप्त फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद भी निर्धारित समय सीमा के भीतर जरूरी इंतजाम नहीं किए गए तो संबंधित होटल को अस्थायी रूप से सील करने की चेतावनी दमकल विभाग की ओर से दी गई है।

बताया जा रहा है कि हावड़ा शहर में अतीत में एक के बाद एक आग लगने की घटनाओं के बाद होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए दमकल विभाग ने यह अभियान शुरू किया है। आने वाले दिनों में और भी होटलों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाएगा।

भाजपा ने कोलकाता व हावड़ा नगर निगम चुनाव के लिए गठित की समिति

बंगाल में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने कोलकाता नगर निगम व हावड़ा नगर निगम चुनाव के लिए बकायदा चुनाव समिति का गठन करते हुए प्रभारियों व संयोजकों की नियुक्ति की घोषणा की। पार्टी ने कोलकाता नगर निगम चुनाव का प्रभारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री सुकांत मजूमदार को बनाया है। वहीं, हावड़ा नगर निगम चुनाव के लिए राज्यसभा सदस्य व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा को प्रभारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही दिसंबर तक निकाय चुनाव कराए जाने की बात कह चुके हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिंद्य बनर्जी को कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए गठित समिति का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं, राज्य के उद्योग मंत्री तापस राय को समिति का संयोजक बनाया गया है। काशीपुर-बेलगछिया के विधायक रितेश तिवारी को सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, बाली से विधायक संजय सिंह को हावड़ा नगर निगम के लिए गठित चुनाव समिति का संयोजक बनाया गया है। पार्टी की ओर से दोनों नगर निगमों में संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति तैयार करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। भाजपा की नजर कोलकाता और हावड़ा दोनों नगर निगमों पर है। भाजपा अब दोनों नगर निगमों में उम्मीदवारों के चयन, संगठनात्मक तैयारियों और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेगी।

कोयला जलाकर ईंट पकाने की जरूरत नहीं!

ईंट निर्माण के क्षेत्र में नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू करने की पहल की गई है। अब कोयला जलाकर ईंट पकाने की जरूरत नहीं होगी। इससे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। श्यामपुर के ईंट भट्ठा मालिकों ने प्रदूषण रहित तरीके से ईंट बनाने की पहल की है। इसी सिलसिले में बुधवार को देउलटी में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में दक्षिण कोरिया स्थित एक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ संस्था के अधिकारियों ने प्रदूषण रहित तरीके से ईंट बनाने की तकनीक के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि एक विशेष मशीन के माध्यम से बिजली और केमिकल की मदद से ईंटों का उत्पादन किया जा सकता है। इसमें ईंटों को पकाने के लिए कोयले की जरूरत नहीं होगी। संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ली ने बताया कि एक विशेष मशीन के जरिए 90 प्रतिशत मिट्टी, 9 प्रतिशत सीमेंट और 1 प्रतिशत केमिकल मिलाकर इस तरह की विशेष ईंट तैयार की जा सकती है। इस प्रक्रिया से बनी ईंटें हवा में ही सूख जाएंगी। कच्ची ईंटों को पकाने के लिए कोयला नहीं जलाना पड़ेगा, जिससे कोयले का इस्तेमाल नहीं होगा और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा।

उन्होंने बताया कि झारखंड में पहले से ही इस तकनीक से ईंटों का निर्माण किया जा रहा है। अब इसी तकनीक को श्यामपुर में अपनाने की कोशिश की जा रही है।

श्यामपुर थाना ब्रिक फील्ड ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष तन्मय शी ने कहा कि ईंट निर्माण में मिट्टी एक महत्वपूर्ण कारक है। हर जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं होती। इसलिए श्यामपुर में उपलब्ध मिट्टी के साथ किन चीजों को मिलाने से बेहतर गुणवत्ता की ईंट बनाई जा सकती है, इसकी जांच के लिए मिट्टी को परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। मिट्टी की जांच रिपोर्ट मिलते ही नई तकनीक से ईंट निर्माण शुरू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा झारखंड जाकर ईंधन रहित भट्ठों का भी निरीक्षण किया जाएगा। तन्मय शी ने कहा कि इस नई तकनीक से मिट्टी में अलग-अलग रंग मिलाकर विभिन्न रंगों की ईंटें भी बनाई जा सकती हैं। ये ईंटें देखने में आकर्षक होंगी और इनमें प्लास्टर कराने की भी जरूरत नहीं होगी। इससे निर्माण की लागत में भी बचत होगी।

सनातन सैनिक परिषद की कांवड़ यात्रा में उमड़ा जन सैलाब

रॉबिन दुलोई: हावड़ा में सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर सनातन सैनिक परिषद की ओर से भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में हजारों की संख्या में शिवभक्त शामिल हुए।

श्रद्धालु शिवपुर लंच घाट से गंगाजल लेकर हावड़ा के शालीमार स्थित भड़पाड़ा रोड स्थित बाबा भोलेनाथ के मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया।

इस दौरान शिवभक्त एक समान धार्मिक परिधान में सिर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं में भगवान शिव के प्रति विशेष उत्साह और भक्ति देखने को मिली।

आयोजक प्रमोद सिंह ने बताया कि कई वर्षों से सावन के अंतिम सोमवार को सनातन सैनिक परिषद की ओर से इस कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

शिवपुर गंगा घाट से शुरू होकर यात्रा भड़पाड़ा रोड स्थित बाबा भोलेनाथ के मंदिर तक पहुंचती है, जहां श्रद्धालु गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं।

आयोजकों के अनुसार, इस धार्मिक आयोजन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को एकजुट कर भगवान शिव की आराधना करना और सनातन परंपरा के प्रति लोगों में आस्था एवं श्रद्धा को मजबूत करना है।

हावड़ा नगर निगम चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बढ़ी सक्रियता

नगर निगम चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने हावड़ा में अपनी संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में हावड़ा के शिवपुर थाना अंतर्गत चौड़ा बस्ती इलाके में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 समर्थकों ने समाजवादी पार्टी का झंडा थामकर पार्टी में शामिल होने की घोषणा की।

कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत घोष ने समर्थकों के हाथों में पार्टी का झंडा सौंपा। इस मौके पर इलाके में काफी संख्या में पार्टी समर्थक और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

कार्यक्रम को आगामी नगर निगम चुनाव से पहले पार्टी के संगठ विस्तार और जनाधार मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी नेताओं ने क्षेत्र में संगठन को और मजबूत करने तथा अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया।

गीत

—विजय इस्सर 'वत्स'

(काली-दुर्गा आ सरस्वती)

हम पूजि रहल छवि मूर्ति बना
काली-दुर्गा आ सरस्वती
घर घर बैसलि जीवंत देवि
हुनको देखियौ ने एक रती।
काली-दुर्गा आ सरस्वती...

अम्ब छोड़ि जगदंब कतय
बेटी बहीन उर शक्ति रहय
हिनकर प्रसन्नता सँ भेटय
सुख-शांति,घर लक्ष्मी रहती।
घर घर बैसलि जीवंत देवि
हुनको देखियौ ने एक रती...
काली- दुर्गा आ सरस्वती...

सभ दिव्य छोड़ि देवी पूजल
भव्या सभ कैं भोग्या बूझल
गृह देवी कुपित बनि बैसल
भय क्रुद्ध रूप काली-सती।
घर घर बैसलि जीवंत देवि
हुनको देखियौ ने एक रती...
काली- दुर्गा आ सरस्वती...

पूजा-पाठ आ विधि-विधान
शक्ति समन्वय केर संधान
आत्मा-राम छथिन्ह भगवान
गृह वधू रूप मे भगवती।
घर घर बैसलि जीवंत देवि
हुनको देखियौ ने एक रती...
काली- दुर्गा आ सरस्वती...

सामूहिक रुद्राभिषेक के साथ सजी भक्तिमय मैथिली काव्यधारा

हावड़ा स्थित नागाबाबा आश्रम में मां गंगा के किनारे स्थित शिव मंदिर में बंग मैथिली संघ के तत्वावधान में सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में खुले आकाश के नीचे 'आकाश तर बैसकी' के आयोजन में भक्तिमय मैथिली काव्यधारा का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का संयोजन चंद्रशेखर चौधरी ने किया।

निभा सिंह और रूपेश सिंह के यजमानत्व में पंडित श्रीराम झा मिलन के आचार्यत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भव्य रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की।

इसके बाद विजय इस्सर वत्स के संचालन में कवि गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें कवियों ने अपनी-अपनी रचनाओं एवं गीतों का वाचन और गायन कर उपस्थित लोगों को भावविभोर कर दिया। कवि गोष्ठी में नवीन चौधरी, कामेश्वर झा 'कमल', रंजना झा, अश्विनी झा, अजीत सिंह, मिलन जी, विजय इस्सर 'वत्स' और चंद्रशेखर चौधरी सहित अन्य कवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता के.एन. मिश्र ने की।

कार्यक्रम में पहुंचे सभी श्रद्धालुओं एवं कवियों को भगवा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

धार्मिक अनुष्ठान और साहित्यिक आयोजन के इस अनूठे संगम ने पूरे वातावरण को भक्तिमय और सांस्कृतिक रंग से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

रेलवे ट्रैक पर स्टंट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

सोशल मीडिया के लिए रील बनाने, तस्वीरें खींचने या शार्टकट के लिए रेलवे पटरियों को पार करना जानलेवा साबित हो सकता है। पूर्व रेलवे ने ऐसे खतरनाक व्यवहार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सभी मंडलों में कार्रवाई तेज कर दी है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रेल पटरियां पैदल चलने, शार्टकट अपनाने या सोशल मीडिया के लिए स्टंट करने की जगह नहीं हैं। थोड़ी-सी लापरवाही भी जानलेवा हादसे का कारण बन सकती है।

महाप्रबंधक (जीएम) गीतिका पांडेय के नेतृत्व में पूर्व रेलवे की ओर से लोगों से रेलवे पटरियों से दूर रहने और सुरक्षित रास्तों का इस्तेमाल करने का एक बार फिर आह्वान किया गया है। इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पूर्व रेलवे की ओर से एक बयान में कहा गया कि यात्रियों और आम लोगों की सुरक्षित आवाजाही के लिए फुट ओवरब्रिज, रोड ओवरब्रिज और रोड अंडर ब्रिज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके बावजूद पटरियों को अनधिकृत रूप से पार करने की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा बलों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

पूर्व रेलवे के महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अमिया नंदन सिन्हा ने सभी मंडलों को रेलवे पटरियों पर अनधिकृत आवाजाही और जोखिम भरे इंटरनेट मीडिया स्टंट के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बयान के अनुसार, एक मई से 31 जुलाई 2026 तक चले अभियान में रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत आसनसोल, हावड़ा, मालदा टाउन और सियालदह मंडल में कुल 828 मामले दर्ज किए गए। इनमें 813 मामलों में कार्रवाई करते हुए 853 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मंडलवार आंकड़ों के अनुसार, आसनसोल मंडल में 152 अभियोजन मामले दर्ज हुए और 156 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हावड़ा मंडल में 96 मामले दर्ज हुए और 97 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मालदा मंडल में 298 अभियोजन मामलों में 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

NAME CHANGE

I, Ramjee Ram, son of Lakhi Ram, residing at Shankarpur, Odrai, Ghazipur, Uttar Pradesh-275202, do hereby solemnly affirm and declare that my son's actual name is Shaurya Kumar DOB: 15th February 2011 and **Shaurya Kumar** and **Shaurya Kumar Bharti** is the same and one identical person via affidavit in the Court of Ld Judicial Magistrate 1st Class at Alipore dated 13th August 2026.

गुरु के सम्मान में मनाया जाता है शिक्षक दिवस

पुष्पा साव: भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने का अवसर है। शिक्षक विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि उन्हें अनुशासन, संस्कार, मेहनत और जीवन में सही रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस

भारत में शिक्षक दिवस महान शिक्षाविद, दार्शनिक और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था।

डॉ. राधाकृष्णन का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। वह एक महान शिक्षक और विद्वान के रूप में भी जाने जाते थे। उनके विचारों में शिक्षा को समाज और राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण आधार माना गया।

1962 से हुई शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत

भारत में शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा 1962 में शुरू हुई। जब डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने, तब उनके विद्यार्थियों और प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई थी। इस पर उन्होंने अपने जन्मदिन को अलग से मनाने के बजाय इसे शिक्षकों के सम्मान में मनाने का सुझाव दिया। इसके बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई।

शिक्षक क्यों हैं समाज के लिए महत्वपूर्ण?

किसी भी देश के भविष्य को तैयार करने में शिक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अधिकारी, नेता या किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्ति बनने से पहले हर विद्यार्थी एक शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करता है।

एक शिक्षक विद्यार्थी की गलतियों को सुधारता है, उसकी प्रतिभा को पहचानता है और उसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए शिक्षक को समाज में मार्गदर्शक और राष्ट्र निर्माता की भूमिका में देखा जाता है।

स्कूल-कॉलेजों में होते हैं विशेष कार्यक्रम

शिक्षक दिवस के अवसर पर देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हैं और कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, निबंध प्रतियोगिता तथा सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं।

कई शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी इस दिन अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें उपहार और शुभकामनाएं भी देते हैं।

भारत रत्न से सम्मानित हुए थे डॉ. राधाकृष्णन

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे।

शिक्षक दिवस हमें क्या संदेश देता है?

शिक्षक दिवस केवल एक दिन शिक्षकों को धन्यवाद देने का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमें शिक्षा और शिक्षकों के महत्व को समझने का संदेश देता है। शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य को आकार देने के साथ-साथ एक बेहतर समाज और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

इसलिए 5 सितंबर का दिन हर विद्यार्थी के लिए अपने शिक्षकों को सम्मान देने और उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने का विशेष दिन है।

हावड़ा नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक

हावड़ा और कोलकाता नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोलकाता में पार्टी की बैठक पहले ही संपन्न हो चुकी है। हावड़ा के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल में आयोजित पार्टी की तैयारी बैठक में भाजपा के राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा, राज्य के मंत्री उमेश राय, बाली के विधायक संजय सिंह, शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रुद्रनील घोष, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित अन्य मंडल अध्यक्ष उपस्थित थे। पार्टी की ओर से बताया गया कि पांच मंडल अध्यक्ष बैठक में अनुपस्थित रहे।

हावड़ा नगर निगम के 50 वार्डों को परिसीमन के माध्यम से बढ़ाकर वर्तमान में 68 वार्ड कर दिया गया है। भाजपा का दावा है कि सभी 68 वार्डों के लिए पहले ही वार्ड समिति और चुनाव समिति गठित की जा चुकी है। इन्हीं समितियों के अध्यक्षों को लेकर सोमवार की बैठक आयोजित की गई।

भाजपा की ओर से बताया गया कि प्रत्येक वार्ड की स्थानीय समस्याओं और नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में संबंधित इलाका किस प्रकार पिछड़ा हुआ है, इसे उजागर करते हुए अलग-अलग 'चार्टशीट' जारी की जाएगी। इन चार्टशीट को तैयार करने का काम पहले ही शुरू हो चुका है।

इसके साथ ही हावड़ा नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा अलग से घोषणापत्र तैयार करेगी। पार्टी ने कहा है कि घोषणापत्र केवल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि हावड़ा के प्रतिष्ठित नागरिकों से भी सुझाव लिए जाएंगे। उनके घर जाकर हावड़ा के विकास के लिए किन कार्यों की आवश्यकता है और घोषणापत्र में किन मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए, इस संबंध में राय ली जाएगी। भाजपा का दावा है कि यह केवल पार्टी का घोषणापत्र नहीं, बल्कि वास्तविक अर्थों में जनता का घोषणापत्र होगा।

स्वत्वाधिकारी 'बात हिन्दुस्तान की' (पाक्षिक) पेपर के लिए मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती सोनी कुमारी झा, 23 रामकुमार गांगुली लेन, 2रा तल्ला कमरा नं. 203, पोस्ट- बी, गार्डेन, शिवपुर, हावड़ा-711103 (प. बंगाल) फोन नं.: 8902221434 से प्रकाशित एवं एल.एस पब्लिकेशन्स प्रा. लि.4, कैनल वेस्ट रोड, कोलकाता -700015 से मुद्रित, सम्पादक- वैद्यनाथ झा, फोन-9798848926 पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी, ईमेल/वेबसाईट - www.baathindustanki@gmail.com
(Owner, Printer & Publisher of 'Baat Hindustan ki' Smt. Soni Kumari Jha, 223, Ramkumar Ganguly Lane, 2nd floor, room no-203, PO_R.Garden, Shibpur, Howrah-711103, Mo. 9798848926 & Printed from L.S. publication private limited.4 no, canel west road, Kolkata 700015, Editor: Baidyanath Jha Mo. 9798848926, Email/Website: www.baathindustanki@gmail.com